भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4301
29 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

मत्स्य किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां

4301. श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों/कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विशेष रूप से उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज और मत्स्य उत्पादों के निर्यात में सुधार के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क): आंध्र प्रदेश राज्य सहित विभिन्न राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत स्थापित करने के लिए परिकल्पित मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का विवरण नीचे दिया गया है;

i. मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से बिहार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना नीली क्रांति- मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन के अंतर्गत प्रायोगिक आधार पर 05 एफएफपीओ स्थापित करने में सहायता प्रदान की। आंध्र प्रदेश में एक एफएफपीओ सहित 5 मत्स्य किसान उत्पादक संगठन पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

ii. वित्तीय वर्ष 2020-21 से कार्यान्वित प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरों और मत्स्य पालक किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि करने के लिए मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मत्स्यपालन विभाग ने अब तक वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 92 एफएफपीओ स्थापित करने की मंजूरी दी है, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से 70 एफएफपीओ और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के माध्यम से 22 एफएफपीओ शामिल हैं और इनमें से एनसीडीसी ने आंध्र प्रदेश के लिए 5 एफएफपीओ आवंटित किए हैं।

iii. मत्स्यपालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत वित्तीय सहायता से 50 एफएफपीओ की स्थापना के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की सूचना दी है।

(ख) और (ग): पीएमएमएसवाई में अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, मूल्य श्रृंखला और निर्यात में महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने की परिकल्पना की गई है। पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 189.64 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और इसमें 240 प्रसंस्करण संयंत्रों, कोल्ड स्टोरेज, बर्फ संयंत्रों आदि सहित कोल्ड चेन सुविधाओं के विकास के लिए 60.86 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तरी आंध्र प्रदेश में 02 सहित मात्स्यिकी उत्पाद के निर्यात हेतु राज्य के लिए कोल्ड स्टोरेज सहित राज्य में 40.00 करोड़ रुपए प्रति इकाई की लागत के साथ 10 प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना हेतु जलीय कृषि किसान समितियों के चयन के लिए अधिसूचना जारी की है।

*****